

की जांच करने के बाद स्थान की सिफरिश की जानी थी। अप्रैल, 1981 में व्यवहार्य स्थानों को दो समितियों ने संयुक्त रूप से विस्तृत तकनीकी/आर्थिक उपयुक्त अध्ययन किए। इन दो समितियों की रिपोर्ट, जिसमें विस्तृत तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन दिए गए हैं, 31 दिसम्बर, 1981 को प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट की जांच समाप्त होने के तुरन्त बाद गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्रों को वास्तविक स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

स्थान के बारे में विस्तृत जांच दो विशेषज्ञ दलों द्वारा की गईं जिनमें मुख्यतः भारत सरकार के दो उपक्रमों के तकनीकी कार्मिक शामिल थे। अर्थात् मैसर्स प्राजैक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया के। भारत सरकार द्वारा उन पर 1,52,798 रुपये का व्यय किया गया है।

Villages Electrified and to be electrified in M.P.

711. SHRI SUBASH YADAV: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the number of villages which have been electrified so far in Madhya Pradesh State under the Rural Electrification Scheme;

(b) the number of villages in M.P. State particularly in Khargone Distt. which are likely to be electrified during 1982-83; and

(c) funds allocated for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) According to the report received from Madhya Pradesh Electricity Board, out of a total number of 70,883 villages in Madhya Pradesh, 30,018 villages have been electrified upto the end of June 1982.

(b) and (c). The Annual Plan 1982-83 envisages a target for electrification of 2800 villages in Madhya Pradesh. According to the report received

ed from MPEB, the target for 1982-83 includes electrification of 100 villages in Khargone Distt. of M.P. For the year 1982-83 an outlay of Rs. 30.70 crores comprising Rs. 6.50 crores under Normal Development Programme of the State, Rs. 14.20 crores from REC Financing and Rs. 10.00 crores under Revised Minimum Needs Programmes has been allocated for undertaking rural electrification programmes in the State. In addition to this, 1,500 lakhs are expected to be provided under Agricultural Refinance Development Corporation (ARDC) and Special Project Agriculture (SPA) Schemes.

कम वजन के गैस सिलिण्डरों की सप्लाई

712. श्री चन्द्रपाल शंलानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और अन्य जगहों से एल. पी. गैस एजेंसियों द्वारा कम वजन के गैस सिलिण्डरों की सप्लाई किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन (आई. अ. सी.) ने यह सूचित किया है कि उन्हें मेरठ तथा अन्य स्थानों के एल. पी. जी. ग्रहकों से अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) मेरठ स्थित निम्नलिखित इन्डियन डिस्ट्रीब्यूटरों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं :--

1. मैसर्स पासी गैस सर्विस
2. मैसर्स विजयंत गैस सर्विस
3. मैसर्स मेरठ गैस सर्विस
4. मैसर्स पवनपुत एन्टरप्राइसिस

(ग) उपर्युक्त डिस्ट्रीब्यूटरों के बारे में कम भार के एल. पी. जी. सिलिण्डरों पर